प्रेषक,

नितेश कुमार झा, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

उपाध्यक्ष, मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक ०५ जुलाई, 2018

विषयः मा० उच्च न्यायालय,नैनीताल में दायर जनहित याचिका संख्याः 97/2018 सतीश चन्द्र घिल्डियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य सरकार व अन्य की ओर से योजित विशेष अनुज्ञा याचिका के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक एडवोकेएट आन रिकार्ड, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र संख्याः जे०के०बी० 1991 दिनांक, 30.06.2018 जो शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्टांकित है का संदर्भ ग्रहण करें।

2— इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मां उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका संख्याः 97/2018 सतीश चन्द्र घिल्डियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध मां सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.P) में श्री मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मां सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई के दौरान प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बद्ध किये जाने की अनुमित प्रदान की जाती है:—

(1) श्री मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रति सुनवाई पर होने वाला व्यय धनराशि रू० 11.00 लाख (ग्यारह लाख मात्र) का वहन

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(2) मा0 सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली में योजित उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका की प्रभावी पैरवी करने हेतु प्राधिकरण प्रकरण से भिज्ञ वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा, उक्त नामित अधिकारी द्वारा संगत अभिलेखों सहित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आवद्व एडवोकेएट आन रिकार्ड से सम्पर्क एवं समन्वय की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा) सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मा० सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली

2- श्री जे0के0भाटिया, एडवोकेएट आन रिकार्ड, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

3- अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।

4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से, (सुनीलश्री पांथरी) (अपर सचिव।